www.tamsasanket.com
वर्ष: 06 || अंक 38 || लखनऊ
शुक्रवार
08 मई 2026 || पृष्ठ: 04 || मूल्य: ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदय: 05:23
सूर्यास्त: 06:43
अधिकतम: 33°00
न्यूनतम: 24°00

पेज 03

विशेष समाचार
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन है ... >> पेज 02
योगी सरकार में बिना सिफारिश ... >> पेज 04
बेटे की कब्र पर जाकर फूट जेटली...

मोदी नीतीश को हाथ पकड़कर आगे लाए, विभागों के बंटवारे पर मंथन, निशांत को मिल सकता है स्वास्थ्य

निशांत समेत 32 मंत्रियों ने ली शपथ

शपथ -ग्रहण

तमसा संकेत, एजेंसी

पटना। सम्राट चौधरी के CM बनने के 22 दिन बाद आज गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया। मेगा इवेंट में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, LJP(R)-2, HAM और RLM से एक-एक मंत्री हैं। 25 मिनट चले इस कार्यक्रम में एक साथ 5-5 विधायकों ने शपथ ली। पहली बार में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेसी सिंह, और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं। इसके साथ ही सम्राट कैबिनेट में कुल 34 मंत्री हो चुके हैं। JDU कोटे से 2 डिप्टी CM मुख्यमंत्री के साथ पहले ही शपथ ले चुके हैं। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। जदयू ने स्वास्थ्य विभाग की डिमांड की है। समारोह में PM मोदी भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को अपने पास बुलाया। मंच पर उनसे हाथ मिलाया, इस दौरान नीतीश कुमार ने पीएम का कंधा पकड़कर हिला दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सीधे राष्ट्रगान बजाया गया, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम् बजाया जाना था। दो बार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडेय इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, खबर है कि पार्टी में उन्हें बड़ी जगह दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला डाकबंगला चौराहे से आगे बढ़ा है।

>> (शेष पेज 04 पर)

नीतीश बोले- बिहार सुशासन की ऊंचाइयों को छूएगा

नीतीश कुमार ने X पर लिखा- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल विस्तार पर हार्दिक शुभकामनाएं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में सभी माननीय मंत्रीगण जनकल्याण और विकास कार्यों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। बिहार विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

मोदी जी को पहली बार इतने पास से देखा: जीविका दीदी

बसंतपुर गांव की रहने वाली शारदा देवी ने कहा, पीएम मोदी के पटना आने की खबर सुन कर काफी उत्साहित थी। आज इतने नजदीक से पहली बार पीएम मोदी को देखा। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर हम लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री का काफिला गांधी मैदान की ओरआगे बढ़ गया है। रास्ते में समर्थकों ने मोदी-मोदी, जय श्रीराम के नारे लगाए। रोड शो के दौरान पीएम मोदी गाड़ी के अंदर ही रहे, उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिभादन किया।

बीजेपी कोटे से मंत्री

मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े हाईलाइट्स

- जेडीयू से 3 नए चेहरे- निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता। बीजेपी से 4 नए चेहरे- मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंद किशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र।
- सम्राट सरकार का जातीय समीकरण- ईबीसी- 9, ओबीसी-9, दलित-7, सवर्ण-9 और मुस्लिम-1। सम्राट कैबिनेट में 5 महिला मंत्री, इनमें सबसे ज्यादा जदयू से 3 मंत्री हैं।
- शपथ ग्रहण के लिए गांधी मैदान में 3 स्टेज बनाए गए थे।
- बीजेपी ऑफिस के बाहर हरे राम-हरे कृष्ण का भजन-कीर्तन।
- पटना में पोस्टर लगे- भगवामय, अंग, बंग और कलिंग।

निशांत बोले- पिताजी के काम को आगे जारी रखूंगा

मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि पिताजी ने 20 सालों में जो काम किया है, उसे आगे जारी रखूंगा। उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान जो वादे किए हैं, उन सभी वादे को पूरा करूंगा।

ऑपरेशन सिंदूर का एक साल

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया डीपी बदली, ऑपरेशन का लोगो लगाया

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया है। यह पहल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना के साहस को ट्रिब्यूट देने के लिए की गई। अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। 7 मई 2025 को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर में, भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoK) में नौ बड़े आतंकी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया था।

एक और पोस्ट में पीएम लिखते हैंङ्ग एक साल पहले, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेजोड़ साहस, सटीकता और संकल्प का प्रदर्शन किया था। उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया, जिन्होंने पहलगाम में बेकसूर भारतीयों पर हमला करने की हिम्मत की थी। पूरा देश हमारी सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है।ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिक्रिया और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसके अटूट संकल्प को दर्शाया। इसने हमारी सेनाओं के पेशेवरपन, तैयारी और समन्वित शक्ति को भी उजागर किया। साथ ही, इसने हमारी सेनाओं के बीच बढ़ते तालमेल को भी दिखाया और इस बात पर जोर दिया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की भारत की कोशिश ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कितनी ताकत दी है।

वेटिंग टिकट कन्फर्म होगा या नहीं, एआई बताएगा

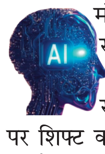

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपने 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को पूरी तरह बदलने जा रहा है। नया सिस्टम AI की मदद से बताएगा कि वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और अगस्त से ट्रेनों को नए अपग्रेड सिस्टम पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। वर्तमान रिजर्वेशन सिस्टम साल 1986 में शुरू हुआ था। पिछले 40 सालों में इसमें कई छोटे बदलाव किए गए, लेकिन अब इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह नया किया गया है, ताकि इसकी क्षमता बढ़ाई जा सके। हां, रेलवन एप एक 'ऑल-इन-वन' प्लेटफॉर्म है। इसमें टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन और रिफंड के साथ-साथ लाइव ट्रेन स्टेटस, प्लेटफॉर्म नंबर, कोच पोजीशन और 'रेल मदद' जैसी सेवाएं शामिल हैं। यात्री इसी एप से खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो सीधे उनकी सीट पर पहुंचता है।

धोखेबाज दलों को जनता दफन करेगी : योगी

देवबंद बदनाम था, फतवे जारी होते थे, देशद्रोहियों ने सिर उठाया तो काम तमाम

तमसा संकेत, एजेंसी

सहारनपुर। 'सहारनपुर पहले फतवों, दंगों और पलायन के लिए जाना जाता था। हर बात पर फतवे जारी होते थे। खाना कैसे खाना है, इस पर भी फतवा जारी होता था। हमने यहां फतवों की संस्कृति नहीं, बल्कि ATS सेंटर दिया है। अब यहां हमारे कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम तय है।' सीएम योगी ने गुरुवार को सहारनपुर को 2131 करोड़ की 325 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए यह बात कही। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर योगी ने कहा- बंगाल में पहली बार भाजपा ने सरकार बनाकर सभी राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाया है। जो समाज के विभाजन के लिए व्यूह रचना कर रहे थे, उन्हें आईना दिखाया है।

इस जीत ने बता दिया कि जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच सक्रिय रहें, तो सरकार दोहराई जाएगी। वरना जनता देश को धोखा देने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में देर नहीं लगाएगी। इससे पहले, योगी ने सहारनपुर में कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र बांटे। कहा- आज मैंने 3 विभागों के करीब 500 नौजवानों को जॉइनिंग लेटर दिए हैं। इनमें सहारनपुर के भी कई नौजवान थे। आज हर वर्ग का व्यक्ति नियुक्ति का हकदार है।

फास्ट न्यूज

लेडी अफसर ने कैदी रह चुके युवक से रचाई शादी

सतना। सतना सेंट्रल जेल की सहायक अधीक्षक फिरोजा खातून ने हत्या के मामले में सजा काट चुके धर्मेंद्र (अभिलाष) नाम के युवक से हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली। 5 मई को छतरपुर जिले के लवकुश नगर में हुए इस विवाह की पूरे इलाके में चर्चा है।अभिलाष उम्रकैद की सजा काट चुका है। करीब 4 साल पहले जेल से रिहा हुआ था। फिरोजा के मुस्लिम परिजन इस रिश्ते से नाराज थे।

शादी की सालगिरह पर महेश जोशी गिरफ्तार

जयपुर। भष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को जयपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन (JJM) में हुए करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले में एसीबी की SIT ने यह कार्रवाई की है। आज ही जोशी की शादी की सालगिरह भी है। DIG डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया- ACB SIT सुबह करीब साढ़े चार बजे सैन कॉलोनी, पावर हाउस रोड, जयपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई थी। यहां महेश जोशी को उनके आवास से पकड़ा गया। सुबह करीब 10 बजे जयपुरिया हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया। मेडिकल टेस्ट के बाद महेश जोशी को एक बार फिर ACB मुख्यालय लाया गया।

हिमाचल के मंदिर में 100 ग्राम सोने का हार चढ़ाया

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के माता ब्रजेश्वरी मंदिर में एक श्रद्धालु ने 100 ग्राम सोने का हार चढ़ाया। महाराष्ट्र के पुणे से आए श्रद्धालु ने यह हार भेंट किया। इसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदिर अधिकारी शिवाली ठाकुर ने बताया कि महाराष्ट्र के पुणे निवासी विनोद एन शर्मा ने यह हार चढ़ाया है। विनोद शर्मा अपने परिवार सहित माता के दरबार में दर्शन करने पहुंचे थे।

जाति तब खत्म होगी जब समाज बदलेगा : भागवत

जनसंख्या नियंत्रण नीति और यूनिफॉर्म सिविल कोड लोगों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते

तमसा संकेत, एजेंसी

मैसूरु (कर्नाटक)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण नीति और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) जैसे कानून लोगों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जाति आधारित राजनीति तभी खत्म होगी, जब समाज जाति के आधार पर सोचना बंद करेगा। भागवत गुरुवार को कर्नाटक के मैसूरु में JSS महाविद्यापीठ में "सोशल हार्मनी ऐज ए कैटलिस्ट फॉर नेशनल डेवलपमेंट" विषय पर लेक्चर के बाद इंटरेक्टिव सेशन में लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने समानता को नारों से नहीं, बल्कि व्यवहार में अपनाने की अपील की। जनसंख्या नियंत्रण और UCC पर सवाल के जवाब में भागवत ने कहा कि RSS सरकार नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन है।

>> (शेष पेज 04 पर)

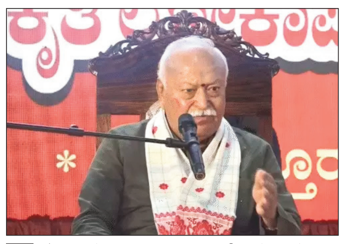

मैसूरु में JSS महाविद्यापीठ में संबोधित करते मोहन भागवत।

> भागवत ने कहा कि जनसंख्या नीति बनाते समय जनसांख्यिकीय संतुलन, महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति तय होने के बाद उसे बिना भेदभाव सभी पर लागू किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में राज्यपाल ने विजय से 118 विधायकों का समर्थन दिखाने को कहा, एआईएडीएमके के 28 विधायक पुडुचेरी शिफ्ट

बंगाल गवर्नर ने विधानसभा भंग की

नोटिफिकेशन

तमसा संकेत, एजेंसी

चेन्नई/कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा भंग कर दी है। लोकभवन से गुरुवार शाम को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसका मतलब है कि ममता कैबिनेट के किसी भी मंत्री के पास अब कोई पावर नहीं रहेगी। ममता ने बुधवार को कहा था कि वे सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी। इधर बंगाल में हावड़ा के पास शिवपुर में भाजपा और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। इससे पहले बुधवार रात को शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दूसरी तरफ तमिलनाडु में सरकार बनने को लेकर पेंच फंसा हुआ है।

>> (शेष पेज 04 पर)

टीवीके समर्थक शपथ ग्रहण समारोह स्थल से निराश लौटे

तमिलनाडु में TVK प्रमुख विजय के 7 मई को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम टल गया है। गुरुवार को चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम पहुंचे सैकड़ों समर्थकों को निराशा हाथ लगी। समर्थक राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी उम्मीद के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे, लेकिन वहां गेट बंद मिले और किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। समर्थकों ने कहा कि वे सुबह से कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। कई लोग सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यहां पहुंचे थे।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच भी सरकार गठन को लेकर चर्चा चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों दलों के नेताओं के बीच बैकचैनल बातचीत चल रही है।

ममता बनर्जी आधी आबादी की आवाज : अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए भाजपा उन्हें निशाना बनाती है। उन्होंने भाजपा को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देख सकती।

पश्चिम बंगाल- कोलकाता में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में परेड ग्राउंड में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। 9 मई को शपथ समारोह होगा। शुक्रवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सीएम का ऐलान हो सकता है।

परिणाम : जनरल की कटऑफ 369 से ऊपर, 20 सवालों पर आपत्ति, 8 के जवाब गलत निकले

यूपी में दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी

12,333 अभ्यर्थी सफल

तमसा संकेत, एजेंसी

प्रयागराज। यूपी में दरोगा भर्ती- 2025 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को जारी हो गया। 12,333 अभ्यर्थी पास हुए हैं। यह संख्या पदों के सापेक्ष लगभग 2.7 गुना है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का कट ऑफ 369.87854 और अनुसूचित जन जाति का कट ऑफ 334.65475 है। महिला बटालियन के लिए महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पीसी) के खाली पदों के सापेक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वर्ग की अनारक्षित श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक 266.40593 और भूतपूर्व सैनिक वर्ग की अनारक्षित श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ 223.48777 है। अभ्यर्थियों ने 160 सवालों में से 20 पर आपत्ति जताई थी। 8 सवाल के विकल्प गलत निकले हैं। हालांकि अवसरवादी के 'पंडित' विकल्प वाले सवाल में कोई बदलाव नहीं किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन (DV), शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से गुजरना होगा।

पंडित वाले सवाल में कोई बदलाव नहीं

दरोगा भर्ती परीक्षा में अवसरवादी विकल्प से जुड़े सवाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सवाल के विकल्प में 'पंडित' देने पर खूब सियासत हुई थी। तब भर्ती बोर्ड से जुड़े एक अधिकारी ने कहा था कि सवाल पूछा गया है। उसका विकल्प दिया गया है, न कि पर्यायवाची। हमेशा 3 विकल्प गलत होते हैं। ऐसे में पंडित शब्द को अवसरवादी से कैसे जोड़ा जा सकता है?

20 सवालों पर आपत्ति, बोर्ड ने 3 बड़े फैसले लिए

अभ्यर्थियों ने 20 सवालों पर आपत्ति जताई थी। भर्ती बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों से परीक्षण कराने के बाद तीन बड़े फैसले लिए हैं।

8 सवाल के विकल्प गलत निकले

8 सवालों के जवाब में जो विकल्प दिए गए थे, वो गलत थे। इसलिए बोर्ड ने सवालों को रद्द कर दिया है। इसके नंबर सभी को दिए गए हैं।

8 सवाल ऐसे पाए गए, जिनमें एक से ज्यादा जवाब सही थे

बोर्ड ने फैसला लिया है कि अगर अभ्यर्थी ने उन सही विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प चुना होगा तो उसे उस सवाल के पूरे नंबर दिए जाएंगे।

उदाहरण: अगर किसी सवाल में A और C दोनों सही माने गए, और आपने A चुना है तो भी नंबर मिलेगा, C चुना है तो भी नंबर मिलेगा।

6 सवालों के विकल्प बदले गए

भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, 4 सवालों के विकल्प में बदलाव किया गया है। ये ऐसे सवाल थे, जिसमें अभ्यर्थियों के विकल्प सही थे और परीक्षक की ओर से निर्धारित विकल्प गलत था। ऐसे चारों सवालों के विकल्प अभ्यर्थियों की आपत्तियों को जांचने के बाद बदल दिए गए।

जीआरपी कांस्टेबल की पीट-पीटकर हत्या

छेड़छाड़ के आरोप में बीच सड़क पर बांधकर पीटा

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

भुवनेश्वर। ओडिशा के खुर्दा जिले में लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर एक जीआरपी कांस्टेबल सौम्य रंजन स्वाईं की हत्या कर दी। घटना उस समय हुई जब सौम्य रंजन अपने साथी के साथ किसी आधिकारिक काम से रेलवे एडीजी से मिलने जा रहे थे। आरोप है कि सौम्य रंजन और ओम प्रकाश ने बुधवार को रास्ते में दो युवतियों पर अभद्र टिप्पणी की। उनकी बाइक ने स्कूटी सवार दो महिलाओं को टक्कर भी मारी, जिससे महिलाएं दूर तक घसीटती चली गईं। सौम्य रंजन पिछले 12 सालों से कटक जीआरपी में कांस्टेबल था। सौम्य रंजन की मां ने कहा कि उनका बेटा अपने साथी ओम प्रकाश के साथ एडीजी से मिलने जा रहा था, लेकिन लोगों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला। परिवार का आरोप है कि पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे।

> सौम्य को युवतियों पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में भीड़ बांधकर गाड़ी में ले गई।

सम्पादकीय

प.बंगाल और तमिलनाडु में कौन बनेगा मुख्यमंत्री

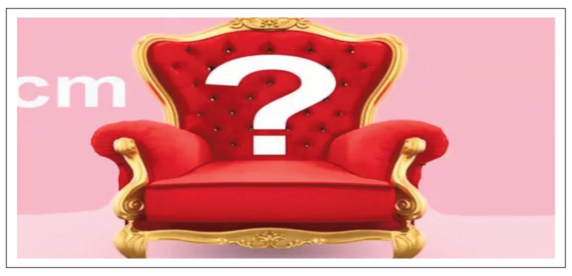

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब सरकार गठन की हलचल तेज है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में प.बंगाल और तमिलनाडु हैं। प.बंगाल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है और वहां अब तक यही माना जा रहा है कि सुवेन्दु अधिकारी ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। क्योंकि पिछले सत्र में वे नेता प्रतिपक्ष थे। लेकिन मोदी-शाह की चौंकाने वाली राजनीति के कारण इस बारे में स्पष्ट तौर पर कोई दावा नहीं किया जा रहा। यह भी कहा जा रहा है कि किसी महिला चेहरे को भाजपा आगे लाएगी। इससे एक तरफ ममता बनर्जी के मुकाबले एक महिला नेता को बंगाल में खड़ा किया जाएगा और दूसरी तरफ भाजपा अपने नारी वंदन वाले सियासी पैंतरे को भी धार देगी। हालांकि भाजपा की सरकार गठन की तैयारियों के बीच मंगलवार को जब ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, तो इस पर सवाल उठने शुरु हो गए कि क्या ऐसा संभव है कि कोई विधानसभा चुनाव हारने के बाद पद से हटने तैयार न हो। लेकिन ममता बनर्जी ने एक बात और भी कही थी कि अब वे आजाद चिड़िया की तरह हैं, जिन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वे अब सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ेंगी। यानी इस्तीफा न देने वाली बात अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के संकेत के तौर पर कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 172 की व्यवस्था है कि किसी राज्य में पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद विधानसभा स्वतःभंग हो जाती है। वर्तमान बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 8 मई 2021 से शुरू हुआ था और यह 7 मई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद राज्यपाल को नयी विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अर्थात नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और नयी सरकार का गठन किया जाएगा। कल के बाद ममता बनर्जी का यूं भी सरकार पर कोई हक नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के पास सैद्धांतिक शक्ति होती है, जिसके अनुसार, मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक अपने पद पर रहता है। यानी विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने और चुनाव हारने के बाद भी अगर ममता बनर्जी कहें कि मैं पद से नहीं हटूंगी तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि खुद ममता बनर्जी ऐसे असंवैधानिक तरीके आजमा कर अपने संघर्ष को कमजोर नहीं करेंगी। अब कल के बाद भाजपा किसे विधायक दल का नेता चुनती है, यह देखना होगा। इधर तमिलनाडु में भी सरकार गठन की पहल खासी दिलचस्प हो चुकी है। इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसके नेता थलापति विजय दो-दो सीटों से जीते। लेकिन टीवीके बहुमत के 118 के आंकड़े को पार नहीं कर सकी। टीवीके के पास 108 सीटें हैं और विजय जब एक सीट से इस्तीफा देंगे तो टीवीके के पास 107 सीटें रहेंगी। ऐसे में उसे सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का सहयोग लेना होगा। नतीजों वाले दिन ही विजय के पिता चंद्रशेखर ने कांग्रेस को साथ आ कर सरकार बनाने का न्यौता दिया था। राहुल गांधी ने विजय को जीत की बधाई भी दी थी। इसके अलावा विजय ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने फैसला तमिलनाडु राज्य ईकाई पर छोड़ दिया था। अब तमिलनाडु कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए टीवीके को समर्थन देने पर सहमति जताई है। एआईसीसी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चौडनकर की तरफ से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, 'हमारा समर्थन इस शर्त पर होगा कि टीवीके इस गठबंधन से उन सांप्रदायिक ताक़तों को दूर रखे जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करतीं। इस तरह कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर विजय एआईएडीएमके या बीजेपी की तरफ झुकाव दिखाते हैं तो वह समर्थन वापस भी ले लेगी। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद कम ही है। ध्यान रहे कि तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में थी और पिछले विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव भी दोनों ने मिल कर लड़ा था। राहुल गांधी और एम के स्टालिन के बीच हमेशा मधुर संबंध दिखे हैं, दोनों नेताओं ने कई मौकों पर एक-दूसरे की सार्वजनिक तौर पर तारीफ की है। लेकिन अब डीएमके के खिलाफ खड़ी टीवीके को समर्थन देने पर बहुत से लोग कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी पर तंज कसे जा रहे हैं कि वो खुद अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं तो किस तरह विपक्षी एकता की बात कर सकते हैं। लेकिन यहां सवाल व्यावहारिकता का है। अगर कांग्रेस ने टीवीके के साथ आने का फैसला नहीं किया होता तो फिर भाजपा यहां पर महाराष्ट्र, हरियाणा या गोवा जैसा खेल खेलती और एआईएडीएमके के सहारे विधायकों को तोड़-फोड़ कर सरकार में आ जाती। भाजपा के हालिया इतिहास के बाद ऐसी आशंका निराधार नहीं है। शायद टीवीके भी इस बात को जानती है इसलिए उसने अपने सभी विधायकों को रिसॉर्ट भेज दिया है। वैसे डीएमके नेता कनिमोझी ने कहा है कि कांग्रेस को जो सही लगा उसने वही किया। टीवीके भी धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करती है, ऐसे दलों का स्वागत है। इस बयान से अनुमान है कि राज्य में भले अब डीएमके और कांग्रेस साथ दिखाई न दें, लेकिन लोकसभा में दोनों साथ हैं। वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पर बने गठबंधन में कई बार घटक दल राज्य स्तर पर एक-दूसरे के बरक्स खड़े होते हैं, तो कांग्रेस ने टीवीके के साथ जाकर कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिस पर सवाल उठाए जाएं। कांग्रेस के लिए फायदे की बात ये है।

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन है वैचारिक बदलाव का संकेत

> इस चुनाव में हिंदी भाषी मतदाताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में हिंदी भाषी समाज का प्रभाव बढ़ा है। यह वर्ग लंबे समय से स्वयं को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करता रहा था। भाजपा ने इस वर्ग को संगठित करने में सफलता प्राप्त की।

पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों को केवल एक राजनीतिक दल की जीत या हार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह परिणाम उस वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरे हैं, जो लंबे समय से बंगाल की राजनीति के भीतर सुलग रहा था। वर्षों तक बंगाल को एक ऐसे राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां कथित रूप से जाति, धर्म और पहचान की राजनीति नहीं चलती, बल्कि विचारधारा, वर्ग-संघर्ष और बंगालियत की राजनीति प्रभावी रहती है। किंतु 2026 के चुनाव परिणामों ने इस स्थापित धारणा को गहराई से चुनौती दी है। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान में आए परिवर्तन का भी संकेत है। मतदाता अब केवल भावनात्मक नारों या वैचारिक रोमांटिसिज्म के आधार पर मतदान नहीं कर रहा, बल्कि वह अपनी सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और भविष्य को भी ध्यान में रख रहा है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता को अनेक विश्लेषक एक प्रकार के "सांस्कृतिक पुनर्जागरण" के रूप में देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में "बंगाली अस्मिता" और "हिंदू पहचान" के बीच एक वैचारिक द्वंद्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। तृणमूल कांग्रेस ने स्वयं को बंगाल की संस्कृति और क्षेत्रीय गौरव का संरक्षक बताया, जबकि भाजपा ने राष्ट्रीयता, हिंदुत्व और सांस्कृतिक चेतना को अपने राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया। वास्तव में बंगाल की ऐतिहासिक चेतना कभी संकुचित नहीं रही। यह वही भूमि है जहाँ से स्वामी विवेकानंद, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, रवींद्रनाथ ठाकुर और नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे महापुरुषों ने भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा दी। "वंदे मातरम्" का उद्घोष भी इसी भूमि से निकला। इसलिए जब बंगाल में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता की चर्चा होती है, तो वह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि भावनात्मक और ऐतिहासिक संदर्भ भी ग्रहण कर लेता है। भाजपा ने इसी ऐतिहासिक चेतना को पुनः

जागृत करने का प्रयास किया। दुर्गापूजा, रामनवमी, हनुमान जयंती और हिंदू धार्मिक प्रतीकों को लेकर जिस प्रकार की राजनीतिक बहसें पिछले वर्षों में सामने आईं, उन्होंने हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को यह महसूस कराया कि उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां राजनीतिक विवाद का विषय बन रही हैं। परिणामस्वरूप एक बड़ा वर्ग अपनी पहचान के प्रश्न पर अधिक मुखर हुआ। पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से अल्पसंख्यक वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती रही है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि ममता बनर्जी सरकार ने संतुलित शासन के बजाय तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। चाहे इमाम भत्ता का मुद्दा हो, धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासनिक निर्णय हों या सीमावर्ती जिलों में बदलता जनसांख्यिकीय संतुलन-इन सभी विषयों ने धीरे-धीरे हिंदू समाज के भीतर असंतोष को जन्म दिया। यह असंतोष केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी था। अनेक लोगों को यह लगने लगा कि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता का अभाव है। भाजपा ने इसी भावना को राजनीतिक रूप दिया। उसने यह संदेश देने का प्रयास किया कि उसकी राजनीति केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि "सांस्कृतिक सुरक्षा" स्थापित करने की राजनीति है। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के दौरान "जय श्रीराम" जैसे नारे केवल धार्मिक उद्घोष नहीं रहे, बल्कि वे एक प्रकार के राजनीतिक प्रतिरोध और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक बन गए। वस्तुतः भाजपा ने हिंदी भाषी और स्थानीय हिंदू समाज के बीच एक वैचारिक सेतु बनाने का प्रयास किया। उसने यह संदेश दिया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर है। यही कारण है कि बंगाल के अनेक क्षेत्रों में भाजपा को व्यापक समर्थन मिला। पश्चिम बंगाल कभी वामपंथ का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। वर्ग-संघर्ष, श्रमिक राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा यहाँ की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा रही। लेकिन समय के साथ यह विचारधारा जमीन से कटती चली गई। वामपंथी दल जनता की नई आकांक्षाओं, युवाओं की उम्मीदों और बदलते सामाजिक यथार्थ को समझने में असफल रहे। आज का युवा केवल वैचारिक भाषण नहीं चाहता- वह रोजगार, सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्मान और विकास चाहता है। यही कारण है कि वामपंथ धीरे-धीरे राजनीतिक हाशिये पर पहुँच गया। भाजपा ने इस खाली स्थान को भरते हुए स्वयं को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता को अनेक लोग डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों से भी जोड़कर देख रहे हैं। डॉ. मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विभाजनकारी राजनीति का विरोध किया और राष्ट्रीय एकात्मता को सर्वोपरि माना। बंगाल की राजनीति में भाजपा का उभार कहीं न कहीं उसी विचारधारा की पुनर्स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि बंगाल अब केवल क्षेत्रीय राजनीति का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वह पुनः राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व करेगा। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या इन चुनाव परिणामों को "हिंदू पुनर्जागरण" कहा जा सकता है? इसका उत्तर पूरी तरह सरल नहीं है, किंतु इतना स्पष्ट है कि हिंदू समाज के भीतर अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक नई जागरूकता अवश्य उत्पन्न हुई है। यह जागरूकता केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक अभिव्यक्ति का भी रूप ले रही है। हालांकि किसी भी लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक चेतना सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों के साथ संतुलित रहे। यदि पहचान की राजनीति संवाद और समावेशिता के बजाय टकराव का रूप लेती है, तो वह लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए बंगाल के इस परिवर्तन को केवल विजय उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी और आत्ममंथन के अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। भाजपा की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल अब राजनीतिक रूप से "अपवाद" नहीं रहा। यहाँ भी वही प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं जो देश के अन्य हिस्सों में प्रभावी हैं-सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सामाजिक संतुलन। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। यदि भाजपा वास्तव में बंगाल में एक नए युग की शुरुआत करना चाहती है, तो उसे केवल वैचारिक नारों तक सीमित नहीं रहना होगा। उसे रोजगार, उद्योग, शिक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर ठोस कार्य करना होगा। बंगाल की धरती ने हमेशा भारत को विचार, साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रवाद की नई दिशा दी है। आज फिर इतिहास एक नए मोड़ पर खड़ा है। आने वाला समय तय करेगा कि यह परिवर्तन केवल राजनीतिक लहर साबित होगा या वास्तव में बंगाल के सांस्कृतिक और वैचारिक पुनर्जागरण का आधार बनेगा।

■ ललित गर्ग

जन सुराज का...

ओ.पी.पाल

लहूलुहान लोकतंत्र: क्या नई सरकार बदलेगी बंगाल का हिंसक इतिहास?

पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर एक बदलाव की उम्मीद जताई है लेकिन यदि यह बदलाव केवल 'चेहरों' का है और 'संस्कृति' वही हिंसक रही, तो बंगाल के विकास की राह फिर से अवरुद्ध हो जाएगी। हिंसा का असली कारण केवल 'हताशा' या 'अहंकार' नहीं है बल्कि वह राजनीतिक व्यवस्था है, जहाँ असहमति के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई घटना नहीं है। 1970 के दशक से लेकर वामपंथी शासन और फिर टीएमसी के कार्यकाल तक, सत्ता का रास्ता हमेशा संघर्षों से होकर गुजरा है। मसलन पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'सत्ता' और 'हिंसा' का रिश्ता दशकों पुराना है यानी पश्चिम बंगाल की का शोर अक्सर हिंसा की गूंज के राजनीति में 'सत्ता परिवर्तन' साथ सुनाई देता है लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जो मंजर दिखा, उसने राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ दिया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं हैं। यहां राजनैतिक दल का कार्यकर्ता केवल समर्थक नहीं, बल्कि एक योद्धा की भूमिका में होता है। शायद यही कारण है कि भाजपा और टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद की कमी और एक-दूसरे के प्रति 'शत्रुतापूर्ण' भाषा ने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को और उग्र कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। यदि भाजपा को राज्य में सुशासन

स्थापित करना है, तो उसे 'प्रतिशोध की राजनीति' से ऊपर उठकर कानून का शासन स्थापित करना होगा। वहीं टीएमसी को एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में जनादेश को स्वीकार कर अपने कार्यकर्ताओं को शांत करना होगा। प्रशासन को चाहिए कि वह दोषियों की पहचान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपद्रवियों को किसी भी राजनीतिक संरक्षण के बावजूद जेल भेजा जाए। चुनाव खत्म होने के बावजूद 700 से अधिक कंपनियां राज्य में रोकी गई हैं, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। अक्सर पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान तो सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, लेकिन परिणामों के बाद स्थानीय पुलिस पर अक्सर 'मूकदर्शक' होने के आरोप लगते हैं। इस बार चुनाव आयोग ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। शायद आयोग राज्य में स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है। इसी कारण केंद्रीय बलों को तैनात रखना और उपद्रवियों को सीधे जेल भेजने का फरमान प्रशासन की साख बचाने की आखिरी कोशिश है। बंगाल में के बीरभूम के नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की गला रेतकर हत्या और कोलकाता के न्यू टाउन में भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट-पीटकर हत्या इस हिंसा की क्रूरता को दर्शाती है। पिछले 24 घंटों में भाजपा और टीएमसी दोनों दलों के कम से कम 2-2 कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। कोलकाता के न्यू मार्केट में टीएमसी दफ्तर को बुलडोजर से गिराना और आसनसोल, सिलीगुड़ी, हावड़ा में कार्यालयों को आग के हवाले करना यह बताता है कि यह केवल कार्यकर्ताओं की झड़प नहीं, बल्कि 'वर्चस्व' को खत्म करने की लड़ाई है। मुर्शिदाबाद में लेनिन की प्रतिमा को गिराना वैचारिक विद्वेष का प्रतीक बनकर उभरा, जो त्रिपुरा की 2018 की घटनाओं की याद दिलाता है। ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि चुनावी रंजिश अब व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल चुकी है। बंगाल में राजनीतिक दल केवल विचारधारा नहीं, बल्कि 'पाड़ा' (इलाके) पर नियंत्रण के लिए लड़ते हैं। सत्ता बदलते ही निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में इलाके पर कब्जा करने की होड़ मच गई। लेनिन की मूर्ति का गिराया जाना या विपक्षी दल के झंडे फाड़ना केवल संपत्ति का नुकसान नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल में 4 मई 2026 को आए चुनावी नतीजों ने न केवल राज्य की राजनीति को बदल दिया, बल्कि राजनीतिक संघर्ष के एक नए युग की की शुरुआत भी कर दी। जहां 2021 में भाजपा 77 सीटों पर रुकी थी, वहीं इस बार उसने दो-तिहाई बहुमत (207 सीटें) प्राप्त कर राज्य की राजनीति का ध्रुवीकरण अपनी ओर कर लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपने ही गढ़ भवानीपुर से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के हाथों हारना, इस हार की गंभीरता को और गहरा कर देता है। सत्ता का यह विशाल हस्तांतरण केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह वर्षों से चले आ रहे प्रशासनिक और जमीनी ढांचे के ढहने का संकेत भी था। लेकिन इस ऐतिहासिक जनादेश के साथ ही राज्य के हर हिस्से से आगजनी, तोड़फोड़ और हत्याओं की खबरें आने लगीं। ऐसा लगता है कि इस हिंसा के पीछे दो विपरीत मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ काम कर रही हैं, जिन पर दोनों दलों के अपने-अपने तर्क हैं। टीएमसी की हताशा भी स्वाभाविक है जहां 15 साल तक निर्बाध शासन करने के बाद इतनी बड़ी हार को स्वीकार करना टीएमसी के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए कठिन रहा है और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के खत्म होने का डर है। माना जाता है कि जब भी किसी कैडर-आधारित पार्टी की हार होती है, तो उसका निचला स्तर या तो रक्षात्मक हिंसा करता है या पलायन। कई जगहों पर हार के बाद टीएमसी के भीतर गुटबाजी उभरी है, जिसे 'भाजपा के हमले' का नाम देकर दबाने की कोशिश की जा रही है।

भले ही वह...

रामस्वरूप रावतसरे

ममता बनर्जी के यों बौखलाने से क्या होगा? सत्ता तो गई!

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। इन चुनावों में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। दूसरी तरफ 15 सालों से सत्ता में रही टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट से चुनाव हार गई हैं। आमतौर पर नियम यह है कि चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है लेकिन ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने आकर साफ कह दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगी। चुनाव आयोग ने नवनिर्वाचित विधायकों की सूची और परिणाम की आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंप दी है। अब हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या हार के बाद भी कोई मुख्यमंत्री जबरदस्ती पद पर बना रह सकता है। सवाल ये भी है कि अगर कोई इस्तीफा न दे तो क्या संविधान में उसे हटाने का कोई तरीका मौजूद है या नहीं। संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी की निजी जागीर नहीं होती। यह एक तय प्रक्रिया से चलती है। मुख्यमंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक राज्यपाल की सहमति हो। इसे कानून की भाषा में 'डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर' कहते हैं। जब तक मुख्यमंत्री के पास बहुमत रहता है, तब तक राज्यपाल उनके काम में दखल नहीं देते लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं और यह साफ हो जाता है कि सरकार हार गई है, तो मुख्यमंत्री की सारी ताकत खत्म हो जाती है। ऐसे में इस्तीफा न देने की बात कहना सिर्फ राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है. कानूनन इसका कोई आधार नहीं है। यदि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए और फिर भी कुर्सी न छोड़े तो राज्यपाल चुप नहीं बैठते। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत उनके पास बहुत

ताकत होती है। राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री को खुद इस्तीफा देने के लिए कहते हैं। अगर मुख्यमंत्री मना कर देते हैं, तो राज्यपाल उन्हें और उनके मंत्रियों को तुरंत उनके पद से हटा यानी बर्खास्त कर सकते हैं।

ममता बनर्जी भले ही राजभवन जाने से मना कर दें लेकिन वह नई सरकार को बनने से रोक नहीं सकतीं। राज्यपाल सीधे बहुमत पाने वाली पार्टी यानी भाजपा के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाएँगे। कानून के मुताबिक राज्यपाल को नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का पूरा हक है। जैसे ही नया मुख्यमंत्री शपथ लेता है, पुराने मुख्यमंत्री की सारी पावर खत्म हो जाती है। पुलिस और प्रशासन की कमान भी नए मुख्यमंत्री के पास चली जाती है। इसके बाद पुरानी सरकार के पास कोई कानूनी ताकत नहीं बचती और उनका कुर्सी के लिए अड़े रहने का कोई फायदा नहीं होता। बंगाल की विधानसभा का समय 7 मई 26 को खत्म हो रहा है। संविधान कहता है कि जैसे ही विधानसभा का समय पूरा होता है, वह अपने आप खत्म यानी भंग हो जाती है। इसका मतलब है कि 8 मई की सुबह होते ही ममता बनर्जी कानूनी रूप से मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। भले ही वह इस्तीफा दें या न दें, 8 मई से नई सरकार बनाने का काम शुरू करना ही होगा।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

प्रो. महेश चंद गुप्ता

पश्चिमी बंगाल: भय से भरोसे की ओर

पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलने के साथ ही राज्य की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ आया है। पिछले पन्द्रह वर्षों से भय, असुरक्षा और राजनीतिक हिंसा के साये में जी रहे पश्चिमी बंगाल में अब भरोसे की एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। यह जनादेश केवल सरकार बदलने तक सीमित नहीं है बल्कि उस तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ जनता की स्पष्ट नाराजगी का परिणाम है, जिसने राज्य को विकास की मुख्यधारा से दूर कर दिया। बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल इस स्थिति में एकाएक आया? इसके जवाब में यह समझना जरूरी है कि बंगाल की यह स्थिति अचानक नहीं बनी। कभी यह प्रदेश भारत के सांस्कृतिक, बौद्धिक और औद्योगिक विकास का अग्रदूत हुआ करता था। रवींद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष जैसे महान व्यक्तित्वों की कर्मभूमि रहा बंगाल देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था लेकिन स्वतंत्रता के बाद की राजनीति ने इस गौरवशाली विरासत को धीरे-धीरे कमजोर कर दिया। पहले कांग्रेस शासन के दौरान व्यवस्था धीरे-धीरे बिखरने लगी, फिर इसके बाद जब वामपंथी सरकारें आईं तो उन्होंने मजदूर हितों के नाम पर एक ऐसी आर्थिक सोच को बढ़ावा दिया जिस कारण औद्योगिक और तकनीकी विकास ही संदिग्ध हो गया। कम्प्यूटर क्रांति का विरोध इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा। उस दौर में जब दुनिया तकनीक को अपना कर आगे बढ़ रही थी, बंगाल पीछे हटता गया। इसका दुखद परिणाम यह हुआ कि उद्योगों का भरोसा डगमगा गया और निवेश धीरे-धीरे राज्य से बाहर जाने लगा। यह प्रवृत्ति आगे और स्पष्ट हुई जब रतन टाटा सिंगुर में अपना महत्वाकांक्षी नैनो कार प्रोजेक्ट लेकर आए। यह बंगाल के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था जो राज्य को औद्योगिक मानचित्र पर फिर से स्थापित कर सकता था लेकिन राजनीतिक विरोध, आंदोलन और भ्रम के वातावरण ने इस परियोजना को राज्य से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। यह केवल एक वृहद उद्योग की भ्रूण हत्या ही नहीं थी बल्कि बंगाल की साख पर लगा एक ऐसा धब्बा था जिसने देश-विदेश के निवेशकों को यह संदेश दे दिया कि यहां स्थिरता और भरोसे की कमी है। वामपंथी शासन के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में

तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता को उम्मीद थी कि अब राज्य विकास की राह पर लौटेगा लेकिन हालात में सुधार नहीं आया बल्कि कट मनी, सिंडिकेट संस्कृति और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण स्थितियां और बिगड़ती चली गईं। प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती गई और कानून-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। इसका असर सीधे तौर पर राज्य की अर्थ व्यवस्था पर पड़ा। उद्योगों का पलायन तेज हुआ, निवेश घट गया और रोजगार के अवसर घटते गए। सदियों से बंगाल की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मारवाड़ी समाज भी धीरे-धीरे राज्य से बाहर जाने पर मजबूर हो गया। दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्य उनकी पसंद बनने लगे। यह इस बात का प्रमाण है कि बंगाल का कारोबारी माहौल भरोसेमंद नहीं रह गया था। आज स्थिति यह है कि बंगाल में औद्योगिक विकास दर तीन प्रतिशत से भी नीचे सिमट चुकी है जबकि एक जमाने में यह सोलह-सत्रह प्रतिशत थी। टाटा, बिड़ला जैसे नामी घरानों ने अपने उद्योग यहां से ही पूरे देश में फैलाए लेकिन धीरे-धीरे सब यहां से बाहर चले गए। राज्य का आम नागरिक कर्ज के बोझ तले दब चुका है। गांवों में किसान और मजदूर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। रोजगार के अभाव में युवाओं का दूसरे राज्यों की ओर पलायन लगातार बढ़ रहा है। यह उस राज्य के लिए गंभीर स्थिति है जिसने कभी देश को औद्योगिक दिशा दी थी। ममता शासन में कानून-व्यवस्था का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। महिलाओं की सुरक्षा निरंतर खतरे में रही है। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए भी जिस तरह महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाएं सामने आईं, उसने सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। जब समाज का एक बड़ा वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो विकास की कोई भी योजना जमीन पर असरदार साबित नहीं हो सकती। इसी संदर्भ में पीएम नरेंद्र मोदी का कथन याद आता है। मोदी ने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति चिंता का विषय है। रोजगार की कमी के कारण युवाओं का पलायन और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भय, दोनों ही राज्य के लिए गंभीर संकेत हैं। मोदी के इन शब्दों में पीड़ा साफ झलकती है कि जो राज्य कभी देश के औद्योगिक विकास का नेतृत्व करता था, वह आज इस स्थिति में पहुंच गया है। पश्चिमी बंगाल के लिए यह जनादेश एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है जिसके जरिए प्रदेश अपने खोए हुए गौरव को वापस पा सकता है। भाजपा को अपने वादों को पूरा कर यह साबित करना होगा कि राज्य में हुआ बदलाव केवल नारों तक सीमित नहीं है बल्कि उसे वास्तविकता में भी बदला सकता है। राज्य में 'भय से भरोसे' की यात्रा नौ मई को नई सरकार के शपथ लेने के बाद शुरू होनी है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार कितनी दृढ़ इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीतियों और पारदर्शी प्रशासन के साथ आगे बढ़ती है। उसे एक ऐसे राज्य की बागडोर संभालनी है, जहां पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान प्रशासनिक ढांचा कमजोर पड़ा है और आर्थिक गतिविधियां प्रायः ठप हो गई हैं। ऐसे में भाजपा को न केवल इस बिगड़े हुए ढांचे को दुरुस्त करने के लिए ठोस और लगातार प्रयास करने होंगे बल्कि जनता से किए गए वादों पर भी खरा उतरना होगा। अब भाजपा को स्पष्ट और मजबूत जनादेश मिलना एक नई शुरुआत का प्रतीक है लेकिन इस जीत के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी कम नहीं है। भाजपा को विरासत में एक बीमारू राज्य मिला है। उसे एक ऐसे राज्य की बागडोर संभालनी है जहां आर्थिक ढांचा कमजोर हो चुका है, और आम जन का विश्वास डगमगा चुका है। आम जन का भरोसा बहाल करना, नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। प्रदेश के लोग लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी, कमजोर कानून व्यवस्था, आर्थिक ठहराव और पलायन जैसे मुद्दे आम जन जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान करना नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही, विकास का एक स्पष्ट और टिकाऊ मार्ग तैयार करना भी उतना ही आवश्यक होगा ताकि जिस पर चलकर राज्य फिर से प्रगति की राह पर मजबूती से लौट सके।

पहली बार भारत आएगी जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम

अक्टूबर में 3 वनडे और 3 टी-20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, यह पहली बाइलेटरल सीरीज

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अक्टूबर 2026 में तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों की बाइलेटरल सीरीज खेली जाएगी। यह सीरीज कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार जिम्बाब्वे की महिला टीम भारत दौरे पर आएगी। अब तक दोनों देशों के बीच महिला क्रिकेट में कोई आधिकारिक द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज नहीं हुई है।महिला क्रिकेट के बढ़ते दायरे और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की दिशा में इस सीरीज को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर से महिला क्रिकेट को लगातार विस्तार देने की कोशिशें की जा रही हैं और इसी कड़ी में जिम्बाब्वे जैसी उभरती टीमों के साथ बाइलेटरल सीरीज आयोजित की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दौरे की शुरुआत टी-20 सीरीज से होने की संभावना है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। हालांकि अभी तक मैचों की तारीख और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा।भारतीय महिला टीम के लिए यह सीरीज नए खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौका देने का बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है। टीम मैनेजमेंट युवा प्रतिभाओं को परखने और बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने के उद्देश्य से इस सीरीज का उपयोग कर सकता है।

इतिहास में पहली बार आमने-सामने होंगी दोनों टीमें

क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमें किसी इंटरनेशनल फिक्स्चर में आमने-सामने होंगी। अब तक दोनों टीमों के मुकाबले केवल ICC टूर्नामेंट्स या क्वालीफायर्स तक सीमित थे। बाइलेटरल सीरीज के रूप में यह नई शुरुआत होगी। BCCI और जिम्बाब्वे क्रिकेट ने इस सीरीज के जरिए महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

पहली बार होगा महिला क्रिकेट में बाइलेटरल मुकाबला

रिकॉर्ड्स के मुताबिक भारतीय महिला टीम ने भी अब तक जिम्बाब्वे का बाइलेटरल दौरा नहीं किया है। हालांकि पुरुष क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच नियमित सीरीज होती रही हैं, लेकिन महिला क्रिकेट में यह पहली आधिकारिक द्विपक्षीय सीरीज होगी। ऐसे में जिम्बाब्वे की महिला टीम के लिए भारत में खेलना बड़ा अनुभव माना जा रहा है।

पीएसजी लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग फाइनल में

बायर्न म्यूनिख के खिलाफ 1-1 ड्रॉ से बनाई जगह

नई दिल्ली, एजेंसी

पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) ने UEFA चैंपियंस लीग (UCL) के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बुधवार रात एलायंस एरिना में खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे चरण में PSG ने बायर्न म्यूनिख के साथ 1-1 का ड्रॉ खेला। एग्रीगेट स्कोर 6-5 रहने की वजह से डिफेंडिंग चैंपियन PSG टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंच गई है। अब 30 मई को बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में PSG का सामना प्रीमियर लीग की टॉप टीम आर्सेनल से होगा। पिछले हफ्ते पेरिस में हुए पहले चरण के मुकाबले में PSG 5-4 से आगे थी। दूसरे चरण के मैच की शुरुआत में ही तीसरे मिनट में ओस्मान डेम्बेले ने गोल कर टीम की एग्रीगेट बढ़त मजबूत कर दी। ख्विचा क्वाराटशेलिया के पास पर डेम्बेले ने गेंद गोल पोस्ट के ऊपरी हिस्से में पहुंचाकर बायर्न की मुश्किल बढ़ा दी। पूरे मैच में बायर्न म्यूनिख ने वापसी की कोशिश की, लेकिन PSG के डिफेंस ने ज्यादा मौके नहीं दिए। इंजरी टाइम (90+4 मिनट) में हैरी केन ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। केन का इस सीजन में यह 14वां चैंपियंस लीग गोल था। बायर्न को एक्स्ट्रा टाइम में जाने के लिए एक और गोल चाहिए था, जो वह नहीं कर सकी। PSG के पास इतिहास रचने का मौका है। फाइनल जीतने पर वह 1990 के बाद चैंपियंस लीग खिताब डिफेंड (रिटेन) करने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। इससे पहले केवल रियल मैड्रिड लगातार खिताब जीत सकी है।

फास्ट न्यूज

अक्षय कुमार की आंखों की सर्जरी हुई

नई दिल्ली। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के फैंस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि साल में 3-4 फिल्में करने वाले अक्षय कुमार ने फिल्मों और एक्टिंग से एक छोटा सा ब्रेक लिया है। इस ब्रेक की वजह उनकी आखों की सर्जरी है। रिपोर्ट में एक्टर से जुड़े करीबी सूत्र के हवाले से बताया गया है कि अक्षय कुमार की माइनर सर्जरी हुई है, जिसे 6 मई की सुबह किया गया है।

आलिया को घिरता देख रणबीर कपूर पैपराजी पर भड़के

नई दिल्ली। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर एक बार फिर वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। इस बार मामला पैपराजी से जुड़ा है। मुंबई में फिल्म 'दादी की शादी' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान रणबीर फोटोग्राफर्स पर नाराज नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रणबीर पत्नी आलिया भट्ट के साथ स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। यह इवेंट उनकी मां नीतू कपूर की फिल्म 'दादी की शादी' के लिए रखा गया था। जैसे ही दोनों वेन्यू से बाहर निकले, पैपराजी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वीडियो में भीड़ और कैमरों की धक्का-मुक्की से रणबीर असहज दिखे। वायरल क्लिप में रणबीर पैपराजी से पीछे हटने और दूरी बनाए रखने को कहते दिख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि अभिनेता ने आपा खो दिया। कई फैंस का मानना है कि रणबीर आलिया को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे थे।

चौथी तिमाही में पीएनबी का मुनाफा 14% बढ़कर 5,225 करोड़

मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 5 मई को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14% बढ़कर 5,225 करोड़ रहा है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 4,567 करोड़ था। वहीं पिछली तिमाही में ये 5,100 करोड़ था। पूरे वित्त वर्ष यानी 2025-26 में पीएनबी का मुनाफा 1.64% बढ़कर 16904 करोड़ हो गया।

सिंगर ने उठाया थलापति विजय की पार्टी पर सवाल

कार्यकर्ता की सेक्शुअल हैरेसमेंट मामले में गिरफ्तारी हुई

मुबंई, एजेंसी

थलापति विजय की पार्टी TVK (तमिल वेट्री कड़गम) ने तमिलनाडु चुनाव में 108 सीट जीती हैं। चुनाव के नतीजे सामने आने के ठीक बाद उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता की एक नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। खबर सामने आने के बाद साउथ की पॉपुलर सिंगर चिनमई श्रीपदा ने विजय की पार्टी पर सवाल उठाते हुए उनकी आलोचना की है। चिनमई श्रीपदा ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर थलापति विजय की पार्टी के कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर रिएक्ट कर लिखा है, 'जो आदमी यौन अपराध करते हैं, वे अक्सर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें ताकत और बच निकलने का मौका दिखाई देता है। TVK (तमिल वेट्री कड़गम) में एक ऐसे व्यक्ति पर नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप है। पार्टी को पहले उसका सही बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था।' आगे चिनमई श्रीपदा ने लिखा, 'अगर बदलाव का वादा करने वाले लोग भी ऐसी गलतियां करें, तो फिर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उम्मीद कम हो जाती है। बार-बार यह कहना अच्छा नहीं लगता कि "सब एक जैसे हैं", लेकिन ऐसी घटनाएं लोगों को यही सोचने पर मजबूर कर देती हैं।' एक्टर से राजनेता बने थलापति विजय की पार्टी की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है। उन पर 10 साल की बच्ची का यौन शोषण करने का आरोप है। आरोपी की पहचान दिनेश उर्फ पांबू दिनेश के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पीड़िता के परिवार ने इसी हफ्ते शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है।

पोछा लगाया, तलाक की सुनवाई के लिए ऑस्ट्रिया गईं, कहा- मुझे 3 बच्चों से मिलने नहीं दिया

बेटे की कब्र पर जाकर फूट-फूटकर रो पड़ीं सेलिना जेटली

मुबंई, एजेंसी

बॉलीवुड अभिनेत्री Celina Jaitly इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। बीते कुछ महीनों में भाई की यूएई में गिरफ्तारी, वैवाहिक विवाद और तलाक की प्रक्रिया ने उन्हें गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया है। अब ऑस्ट्रिया में चल रही तलाक की सुनवाई के बीच सेलिना का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने दिवंगत बेटे की कब्र पर रोती नजर आ रही हैं। सेलिना इन दिनों ऑस्ट्रिया में हैं, जहां उनके तलाक मामले की सुनवाई चल रही है। अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने दर्द और पारिवारिक संघर्ष को खुलकर बयान किया। वीडियो में सेलिना कब्रिस्तान में अपने दिवंगत बेटे शमशेर की कब्र के पास दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दो हफ्ते उनके लिए बेहद मुश्किल और भावनात्मक रूप से तोड़ देने वाले रहे हैं। पोस्ट में सेलिना ने आरोप लगाया कि अदालत में पेश होने के बावजूद उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को उनसे दूर रखा जा रहा है।

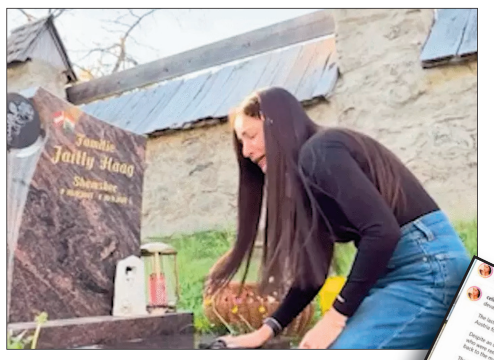

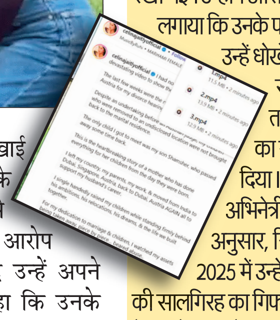

पति पर लगाए गंभीर आरोप

सेलिना ने कहा कि उन्होंने कई बार आपसी सहमति से अलग होने की कोशिश की, लेकिन हर बार अनुचित शर्तें रखी गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति ने उन्हें धोखे में रखकर तलाक का नोटिस दिया। अभिनेत्री के अनुसार, सितंबर 2025 में उन्हें शादी की सालगिरह का गिफ्ट लेने के बहाने बाहर ले जाया गया।

सेलिना ने अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने शादी और परिवार के लिए अपना देश, करियर और निजी जीवन तक छोड़ दिया था। वह भारत से दुबई, सिंगापुर और ऑस्ट्रिया तक कई बार शिफ्ट हुईं ताकि अपने पति के करियर और परिवार को संभाल सकें। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश लगभग अकेले की, लेकिन अब उन्हें बच्चों से दूर किया जा रहा है और उनकी शादी से पहले की संपत्तियों को भी छीनने की कोशिश की जा रही है।

कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है अल्बर्टा

अक्टूबर में वोटिंग संभव, अलगाववादियों ने 3 लाख हस्ताक्षर जुटाए

ओटावा, एजेंसी

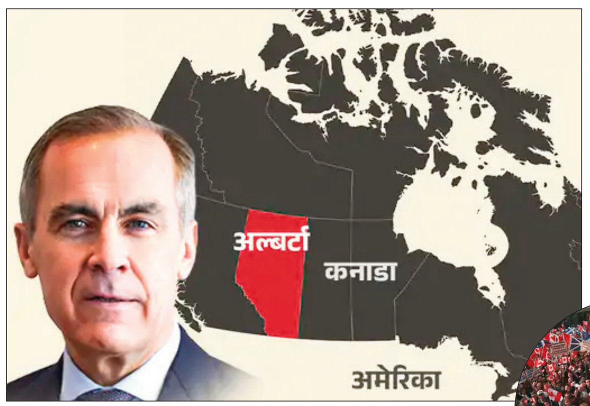

कनाडा के पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा को अलग देश बनने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। अलगाववादियों ने बुधवार को दावा किया है कि उन्होंने इतना समर्थन जुटा लिया है कि अब स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह (रेफरेंडम) कराया जा सकता है। अलगाववादी नेताओं के मुताबिक, उन्होंने करीब 3 लाख हस्ताक्षर चुनाव अधिकारियों को सौंपे हैं, जबकि इसके लिए 1.78 लाख दस्तखत की जरूरत थी। आंदोलन के नेता मिच सिलवेस्ट्रे ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि अब यह लड़ाई अगले चरण में पहुंच गई है। हालांकि इतना समर्थन जुटा लेने का मतलब यह नहीं है कि रेफरेंडम पक्का हो गया है। चुनाव आयोग को पहले इन हस्ताक्षरों की जांच करनी होगी। इस प्रक्रिया पर फिलहाल अदालत के आदेश की वजह से रोक भी लगी हुई है। अगर वोटिंग अल्बर्टा के पक्ष में गई तो यह प्रांत कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है। अल जजीरा के मुताबिक, अगर सभी कानूनी अड़चनें दूर हो जाती हैं, तो प्रांत में 19 अक्टूबर को प्रस्तावित बड़े जनमत संग्रह के साथ अलगाव पर भी वोटिंग कराई जा सकती है। उसी दिन संविधान और इमिग्रेशन जैसे दूसरे मुद्दों पर भी मतदान की योजना है। इस अलगाववादी आंदोलन की जड़ें काफी पुरानी हैं। अल्बर्टा, जहां करीब 50 लाख लोग रहते हैं, लंबे समय से खुद को कनाडा के बाकी हिस्सों से अलग मानता है। यहां के लोग मानते हैं कि उनकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति अलग है, लेकिन फैसले ओटावा में बैठकर लिए जाते हैं।

कनाडा से अलग क्यों होना चाहता है अल्बर्टा

कनाडा के अल्बर्टा में अलग देश बनने की मांग अचानक नहीं उठी है। इसके पीछे कई सालों से चल रही नाराजगी और अलग पहचान की भावना काम कर रही है। सबसे बड़ा कारण आर्थिक है। अल्बर्टा तेल और गैस से भरपूर राज्य है। यहां कनाडा के कुल तेल उत्पादन का लगभग 84% हिस्सा निकलता है। यहां के लोगों को लगता है कि वे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फायदा बाकी कनाडा को ज्यादा मिलता है। उन्हें शिकायत है कि टैक्स का पैसा ओटावा जाकर खर्च होता है।

सर्वे में 30% लोग ही अलग देश के पक्ष में

अगर यह प्रस्ताव वोटिंग तक पहुंचता है, तो लोगों से सीधा सवाल पूछा जाएगा कि क्या अल्बर्टा कनाडा से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनना चाहिए। लेकिन सर्वे बताते हैं कि अभी सिर्फ करीब 30 प्रतिशत लोग ही इसके समर्थन में हैं, यानी जनमत संग्रह पास होना भी आसान नहीं है। हालांकि अलगाववादियों का मानना है कि यह आंकड़ा वोटिंग के दौरान बढ़ने वाला है। अल्बर्टा की प्रीमियर डेनिएल स्मिथ ने कहा है कि अगर जरूरी हस्ताक्षर पूरे होते हैं तो वह वोटिंग आगे बढ़ाएंगी, लेकिन वह खुद कनाडा से अलग होने के पक्ष में नहीं हैं।

ट्रम्प सरकार पर अलगाववादियों को बढ़ावा देने का आरोप

इसी बीच ट्रम्प सरकार पर अलग देश की मांग कर रहे लोगों को बढ़ावा देने का आरोप है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका के अधिकारी अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से मिलते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा यहां यह भी भावना है कि केंद्र सरकार उनके संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण रखती है।

टाटा संस की लिस्टिंग पर टाटा ट्रस्ट्स में मतभेद

नोएल टाटा आईपीओ के खिलाफ, दो ट्रस्टी लिस्टिंग के पक्ष में

नई दिल्ली, एजेंसी

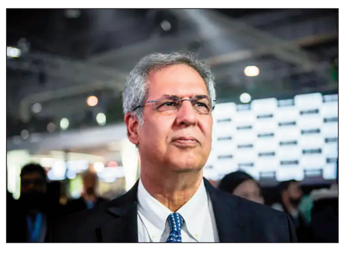

टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी 'टाटा संस' को शेयर बाजार में लिस्ट करने के मुद्दे पर ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट में मतभेद गहरे हो गए हैं। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा इस लिस्टिंग के खिलाफ हैं, जबकि ट्रस्ट के दो बड़े सदस्य आरबीआई के नियमों का हवाला देते हुए आईपीओ लाने के पक्ष में हैं। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा संस की दो-तिहाई हिस्सेदारी है। विवाद की जड़ 'टाटा संस' का IPO है। टाटा ट्रस्ट्स के दो ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह चाहते हैं कि टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाए। उनका मानना है कि इससे कंपनी में पारदर्शिता आएगी। वहीं, नोएल टाटा अभी भी टाटा संस को 'क्लोजली हेल्ड' यानी निजी कंपनी ही बनाए रखना चाहते हैं RBI के नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 से टाटा संस को एक 'सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेन्ट' शैडो बैंक (NBFC) माना जाएगा। नियम यह है कि अगर किसी शैडो बैंक की एसेट साइज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उसे शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य है। टाटा संस इस दायरे में आती है। हां, यह पहली बार नहीं है। 2022 में भी RBI ने टाटा संस को 'अपर-लेयर' NBFC की श्रेणी में रखा था और तीन साल का समय दिया था। तब ग्रुप ने अपना कर्ज रीस्ट्रक्चर करके और खुद को 'नॉन-सिस्टमैटिक' बताकर लिस्टिंग टाल दी थी। लेकिन अब RBI ने वे रास्ते बंद कर दिए हैं।

तेजी : इस साल ₹21 हजार महंगी हो चुकी, सोना ₹377 बढ़कर ₹1.51 लाख के पार निकला

चांदी ₹2318 बढ़कर ₹2.51 लाख किलो पर पहुंची

नई दिल्ली, एजेंसी

सोने-चांदी के दाम में आज यानी 7 मई को बढ़त है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 377 रुपए बढ़कर 1.51 लाख रुपए के पार निकल गया है। वहीं चांदी 2318 रुपए बढ़कर 2.51 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।2026 में सोना अब तक 18 हजार रुपए महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब 1.51 लाख रुपए पर पहुंच गया है। सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी लगातार मजबूती बनी हुई है। औद्योगिक मांग बढ़ने और निवेशकों की खरीदारी के चलते चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचते जा रहे हैं।बाजार जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। त्योहारी सीजन और शादी-विवाह के बढ़ते माहौल के बीच सोने-चांदी की कीमतों में यह बढ़ोतरी आम ग्राहकों की जेब पर असर डाल सकती है।

इस साल चांदी 19 हजार रुपए महंगी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को चांदी 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब बढ़कर 2.51 लाख रुपए पर पहुंच गई है।

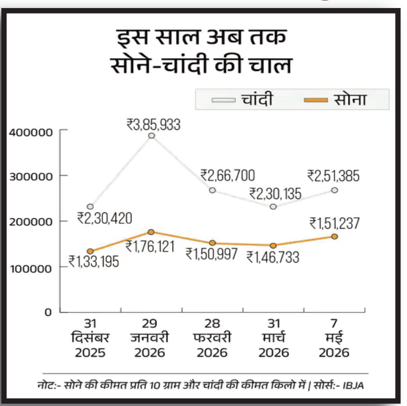

ज्वेलर्स से सोना खरीदते समय इन 2 बातों का रखें ध्यान

1. सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें: हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है।

2. कीमत क्रॉस चेक करें: सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज (जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट) से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होता है।

असली चांदी की पहचान करने के 4 तरीके

- **मैग्नेट टेस्ट:** असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती। अगर चिपक जाए तो फेक है।
- **आइस टेस्ट:** सिल्वर पर बर्फ रखें। असली सिल्वर पर बर्फ तेजी से पिघलती है।
- **स्मेल टेस्ट:** असली सिल्वर में गंध नहीं होती। फेक में कॉपर जैसी गंध आती है।
- **क्लॉथ टेस्ट:** चांदी को सफेद कपड़े से रगड़ें। अगर काला निशान आए तो असली है।

सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की तेजी

मुंबई। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार 7 मई को भी तेजी का माहौल बना हुआ है। पिछले कारोबारी सत्र की मजबूत बढ़त के बाद आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। सुबह के कारोबार में BSE Sensex 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ 78,100 के स्तर के पार पहुंच गया। वहीं NIFTY 50 करीब 50 अंकों की तेजी के साथ 24,400 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। आज के कारोबार में आईटी, ऑटो और मीडिया सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों का रुझान बड़े और मजबूत कंपनियों के शेयरों की ओर बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार को समर्थन मिल रहा है। इससे पहले मंगलवार 6 मई को भी शेयर बाजार में शानदार तेजी दर्ज की गई थी। मंगलवार को बैंकिंग, ऑटो, फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में मजबूत खरीदारी देखने को मिली थी, जिसका असर आज के कारोबार में भी दिखाई दे रहा है।

स्काईरूट एयरोस्पेस बनी देश की पहली स्पेसटेक यूनिकॉर्न

500 करोड़ की फंडिंग के बाद 10 हजार करोड़ हुई वैल्यूएशन

हैदराबाद, एजेंसी

हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एयरोस्पेस ने 60 मिलियन डॉलर यानी करीब 500 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। इस निवेश के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 1.1 बिलियन डॉलर यानी करीब 10 हजार करोड़ पहुंच गई है। यह यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला देश का पहला स्पेस स्टार्टअप है। यह फंडिंग ऐसे समय में आई है जब कंपनी अपने पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-1' की पहली उड़ान की तैयारी कर रही है। स्काईरूट ने हाल ही में हैदराबाद स्थित अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से रॉकेट के महत्वपूर्ण हिस्सों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा भेज दिया है। कंपनी अगले कुछ हफ्तों में इसकी लॉन्चिंग की योजना बना रही है। स्टार्टअप का दावा है कि सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा में भेजने के लिए उनकी सेवाएं दुनिया में सबसे सस्ती होंगी। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेरपालो वेंचर्स और GIC ने किया है। इसमें ग्रीनको ग्रुप के फाउंडर्स और अर्काम वेंचर्स जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। गूगल के शुरुआती निवेशक राम श्रीराम अब स्काईरूट के बोर्ड में शामिल होंगे। इनके अलावा ब्लैकरॉक, प्लेबुक पार्टनर्स और सांघवी फैमिली ऑफिस ने भी निवेश किया है। स्काईरूट ने 2022 में विक्रम-S लॉन्च करके इतिहास रचा था। यह भारत का पहला निजी तौर पर बनाया गया रॉकेट था। विक्रम-1 इसी यात्रा का अगला पड़ाव है, जो पूरी तरह ऑर्बिट तक जा सकेगा। स्काईरूट ने 2022 में विक्रम-S लॉन्च करके इतिहास रचा था। यह भारत का पहला निजी तौर पर बनाया गया रॉकेट था। विक्रम-1 इसी यात्रा का अगला पड़ाव है, जो पूरी तरह ऑर्बिट तक जा सकेगा। जब किसी स्टार्टअप की मार्केट वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 9,400 करोड़ रुपए को पार कर जाती है, तो उसे 'यूनिकॉर्न' कहा जाता है।

सोलर, एविएशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे आधुनिक ट्रेड्स में दिया जा रहा प्रशिक्षण

योगी सरकार में बिना सिफारिश और भ्रष्टाचार के मिल रही नौकरियां : मंत्री कपिल देव अग्रवाल

- अब प्रतिभा और परिश्रम के दम पर मिल रही सरकारी सेवाओं में नियुक्ति
- ईमानदारी और सेवा भावना से दायित्व निभाने का मंत्री अग्रवाल ने किया आह्वान

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में आयोजित भव्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयुष विभाग के लिए चयनित 202 प्रोफेसर, रीडर, चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्स, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के लिए चयनित 272 अनुदेशक तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 7 नर्स, हॉस्टल वार्डन एवं कंपाउंडर शामिल रहे। समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री के स्वागत एवं अभिनंदन के साथ हुआ। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल एवं प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। विशेष आकर्षण के रूप में आईटीआई के विद्यार्थियों द्वारा तैयार 'ब्रह्मोस' मॉडल मुख्यमंत्री को भेंट किया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने जोरदार तालियों के साथ सराहा।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचारमुक्त बनी है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब युवाओं को नौकरी पाने के लिए दलालों और सिफारिशों का सहारा लेना पड़ता था, परिवारों को जमीन तक गिरवी रखनी पड़ती थी, लेकिन आज प्रदेश का युवा केवल अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर सरकारी सेवाओं में चयनित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां प्रदान कर युवाओं के भविष्य को नई दिशा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि देश और प्रदेश विकास एवं सुशासन के नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश तेजी से 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और इसमें कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लगभग 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर 7.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आईटीआई संस्थानों में उद्योगों की मांग के अनुरूप सोलर टेक्नोलॉजी, एविएशन, थ्रीडी प्रिंटिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे आधुनिक ट्रेड्स में प्रशिक्षण देकर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। मंत्री अग्रवाल ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि यह नियुक्ति केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी चयनित युवा पूरी ईमानदारी, समर्पण और सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और विश्वास पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग में अनुदेशक पद पर चयनित नेहा मौर्य, शिवम कुमार दरबार, राजकुमारी, सिकंदर वर्मा, एकता कुशवाहा और रोहित पांचाल नियुक्ति पत्र मिलें। कार्यक्रम में अनुदेशक पद पर चयनित अभ्यर्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। गाजीपुर निवासी अमित थापा, जिन्हें आईटीआई अनुदेशक पद पर नियुक्ति पत्र मिला, ने कहा कि सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने युवाओं का विश्वास मजबूत किया है। चंदौली की अर्चना मौर्य ने कहा कि यह नियुक्ति पत्र उनके लिए केवल रोजगार नहीं बल्कि प्रदेश निर्माण में सहभागी बनने का अवसर है।

सेना का पराक्रम प्रेरणास्रोत : केशव मौर्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की प्रथम वर्षगांठ पर देश के समस्त वीर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके अदम्य साहस, शौर्य एवं राष्ट्रभक्ति को कोटि-कोटि नमन किया है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि पिछले वर्ष आज ही के दिन मां भारती के वीर सपूतों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही करते हुए सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर पूरी दुनिया को भारत की शक्ति, साहस और अटूट संकल्प का परिचय कराया था। उन्होंने कहा कि यह अभियान भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम, वीरता तथा मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च समर्पण का गौरवपूर्ण प्रतीक है। देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए हमारे जवानों का त्याग एवं समर्पण प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मा नरेन्द्र मोदी जी के कुशल एवं दृढ़ नेतृत्व में आज नया भारत आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। भारत अब हर आतंकी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है तथा राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा हेतु हर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

फ्रूट होराइजन 2026 में कृषि और बागवानी के नए आयामों पर मंथन

यूपी को एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। शिवराज सिंह चौहान, सूर्य प्रताप शाही और दिनेश प्रताप सिंह लखनऊ स्थित आईसीएआर-केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान में। में आयोजित 'फ्रूट होराइजन 2026' कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान 'भारतीय फल मूल्य श्रृंखला का वैश्वीकरण' विषय पर आधारित फ्रूट एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर उद्यानिकी, फल उत्पादन, कृषि नवाचार, निर्यात की संभावनाओं और किसानों की आय बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर बागवानी क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। उन्होंने बताया कि आम, अमरूद, तरबूज और आलू उत्पादन में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार ने आम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक दर्जन से अधिक मैंगो बेल्ट घोषित की हैं, जहां बागवानी विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल में भी उत्तर प्रदेश से आम का निर्यात शुरू हुआ था। पहली बार लखनऊ से 20 मीट्रिक टन और सहारनपुर से 50 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया। इसके बाद उद्यान विभाग और राज्य सरकार के प्रयासों से वाराणसी से 1000 मीट्रिक टन से अधिक आम और सब्जियों का निर्यात संभव हुआ है। इससे वाराणसी फल और सब्जियों के बड़े निर्यात केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।

फास्ट न्यूज

इंडिगो की फ्लाइट खराब मौसम में डगमगाई

लखनऊ। दिल्ली से पटना जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-6497 गुरुवार को खराब मौसम के बीच टर्बुलेंस का शिकार हो गई। विमान में सवार यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, फ्लाइट की कमान संभाल रहे पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने सूझबूझ दिखाई। पटना में फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो सकी तो इसे लखनऊ डायवर्ट किया और सुरक्षित लैंडिंग कराई।

भाजपा मुख्यालय पर आधी रात हंगामा, पहुंची पुलिस

लखनऊ। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर आधी रात पहुंचीं सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। मुख्यालय गेट पर महिलाएं जैसे ही प्रदर्शन करने पहुंचीं, तो गेट को अंदर से बंद कर दिया गया। इसके बाद महिलाएं गेट पर ही नारेबाजी करने लगीं। थोड़ी देर के बाद अंदर से भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता भी निकल आए। वे सपा के विरोध और भाजपा के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। कुछ देर में पुलिस पहुंची और सपा की कार्यकर्ताओं को वहां से टांगकर उठा ले गई। गेट पर बैठी महिलाएं भाजपा सरकार और पीएम मोदी-सीएम योगी के मुर्दाबाद का नारा लगा रही थीं। भाजपा के कार्यकर्ता सीएम योगी और पार्टी के जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। मौके पर पुलिस पहुंची जिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कोशिश की।

जिस जिम में डॉक्टर से रेप वहां लेडीज ट्रेनर नहीं

बरेली। बरेली में जिस अल्टीमेट जिम में हिंदू महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, वहां लेडीज ट्रेनर तक नहीं हैं। इस जिम में हाई प्रोफाइल करीब 80 हिंदू महिलाएं वर्कआउट के लिए आती हैं। इन सब को चार पुरुष ट्रेनर ही वर्कआउट कराते थे। रेप के आरोपी संचालक सगे भाई अकरम बेग और आलम बेग गिरफ्तार हैं। पीड़ित महिला डॉक्टर ने बताया- दो साल तक वीडियो दिखाकर अकरम और आलम ने ब्लैकमेल किया।

घर के सामने 3 लोगों ने घेरकर मारा, मृतक के खिलाफ 31 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे

प्रॉपर्टी डीलर की चाकू गोदकर हत्या

तमसा संकेत, एजेंसी

हापुड़। हापुड़ में एक प्रॉपर्टी डीलर को चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। किसी बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद 3 लोगों ने घेर लिया और चाकू से कई वार कर घायल कर दिया। इसके बाद फरार हो गए। चीख सुनकर परिजन दौड़े हुए पहुंचे। गंभीर हाल में उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गुरुवार का यह मामला रामपुर रोड स्थित मोहल्ला अलीनगर का है। मृतक राशिद पर 32 से अधिक आपराधिक मुकदमे थे। एसपी के अनुसार, वह थाने का हिस्ट्रीशीटर था। मृतक और आरोपियों के घर आमने-सामने हैं। मोहल्ले में घर के सामने रहने वाले पड़ोसियों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसी दौरान पड़ोसी राशिद, सुलेमान, सुफियान ने उसे घेर लिया। मारपीट में उस पर चाकू से कई बार हमला किया। चीख पुकार सुनकर जबतक घरवाले पहुंचते, वे फरार हो गए। राशिद जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरों को कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। मोहल्ले में तनाव को देखते हुए भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दिया गया है।

मृतक पर 32 केस, हिस्ट्रीशीटर था

एसपी के अनुसार, मृतक राशिद के खिलाफ 32 आपराधिक केस दर्ज थे। वह हिस्ट्रीशीटर था और उसका हिस्ट्रीशीट नंबर 138A है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। राशिद की मौत की खबर मिलते ही पत्नी रुखसाना बदहवास हाल में अस्पताल पहुंची। घर और अस्पताल में काफी भीड़ जुटी हुई थी। बेटे अयान, मोहम्मद, उमर और बेटी जोया का रो-रोकर बुरा हाल था।

2 आरोपी अरेस्ट, एक फरार

वारदातस्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया- प्रथमदृष्टया तीन भाइयों राशिद, सुलेमान, सुफियान का नाम इसमें सामने आया है। दो आरोपियों राशिद और सुफियान को अरेस्ट कर लिया गया है। जबकि सुलेमान की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे जब्त कर लिए हैं। दो आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। एक अभी फरार है। फिलहाल, हत्या की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ सकी है। हापुड़ नगर के अलीनगर मोहल्ले का राशिद (35) दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था।

चकबंदी कार्यालय के सामने किसानों ने चढ़ाया भगोना

बनाई पूड़ी-सब्जी, अधिकारियों से बोले- हमारी जमीन से माफियाओं को हटाओ

- किसानों ने तय किया है कि उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होगी, तबतक वह यहीं रहेंगे। किसान खाने-पीने की पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं।
- जवाहर भवन परिसर में किसानों ने ईंट इकट्ठा करके भगोने चढ़ा दिए। वह अपने साथ बोरियों में उपले और सूखी लकड़िया लेकर आए हैं।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में चकबंदी कार्यालय के सामने करीबन 100 किसान पहुंच गए। ईंट जोड़कर चूल्हा बनाया, उसपर भगोना चढ़ा दिया। सबने मिलकर पूड़ी-सब्जी बनाई। उनका यह आक्रोश अधिकारियों के खिलाफ था। किसानों का कहना है कि जबतक उनकी जमीनों से माफिया नहीं हटेंगे, तबतक वह चकबंदी कार्यालय के सामने इसी तरह खाना-बनाते खाते रहेंगे। यह माहौल था गुरुवार को जवाहर भवन स्थित चकबंदी आयोग कार्यालय के सामने का। यहां भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) से जुड़े कई जिलों के किसान पहुंच गए। उन्होंने दरी बिछाकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष हरिनाम सिंह कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान अपने साथ लकड़ी , राशन और बड़े-बड़े भगोने लेकर आए हैं। आयुक्त कार्यालय के सामने दरी बिछाकर किसान बैठ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने चूल्हा जला दिया आलू,टमाटर और परवल काटकर सब्जी बना रहे हैं। साथ ही आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हरिनाम ने कहा कि लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है। प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में भूमाफियाओं का जमीनों पर कब्जा है। इस कब्जे में चकबंदी से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह शामिल है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाविद्यालयों को दिया गुणवत्ता शिक्षा और कौशल विकास का मंत्र

आजमगढ़ विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के प्राचार्यों संग समीक्षा बैठक, छात्राओं के आत्मनिर्भर बनने पर दिया जोर

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जन भवन के गांधी सभागार में महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ से सम्बद्ध शासकीय एवं वित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी महाविद्यालयों द्वारा अपने संस्थानों की शैक्षणिक, सहशैक्षणिक एवं कौशल विकास गतिविधियों से संबंधित प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल जी ने कहा कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के लिए स्व-गणना की प्रक्रिया आज से प्रारम्भ हो गई है। उन्होंने सभी से अपील की कि पोर्टल पर जाकर सही एवं तथ्यात्मक जानकारी भरते हुए इस महत्वपूर्ण अभियान में सहभागिता सुनिश्चित करें तथा कार्यक्रम को सफल बनाएं।राज्यपाल जी ने राजकीय महिला महाविद्यालयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। महाविद्यालयों को चाहिए कि वे इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक छात्राओं तक पहुंचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु तकनीकी एवं कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जाएं। कुकिंग, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, प्रौद्योगिकी, योग, संगीत तथा अन्य व्यावसायिक एवं रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देकर छात्राओं को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वे पार्ट टाइम कार्य कर आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकें।राज्यपाल जी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को समय-समय पर राजभवन में आमंत्रित कर उन्हें नैक, एनआईआरएफ तथा अन्य रैंकिंग के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि विभिन्न चुनौतियों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वहां के कुलपति एवं शिक्षकों के प्रयासों से विश्वविद्यालय को नैक में ए प्लस प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ। उन्होंने महाविद्यालयों को भी प्रेरित किया कि वे इन रैंकिंग प्रक्रियाओं में सक्रिय सहभागिता करें तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि निरंतर परिश्रम, टीम भावना एवं योजनाबद्ध प्रयासों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्यपाल जी ने कहा कि अध्यापक समय से महाविद्यालय पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करें तथा विद्यार्थियों को कौशल विकास एवं विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ें।

गोलीबारी : जिस कारोबारी को बंधक बनाकर डाका डाला था, वह बोला- बढ़िया काम हुआ

2 डकैत एनकाउंटर में मारे गए

तमसा संकेत, एजेंसी

मथुरा। मथुरा में कारोबारी को बंधक बनाकर डकैती डालने वाले दो डकैतों को गुरुवार सुबह पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बाबरिया गिरोह के दोनों डकैतों पर 50-50 हजार का इनाम था। मारे गए डकैत में धर्मवीर उर्फ लंबू (35) और राजेंद्र उर्फ पप्पू (55) हैं। दोनों मूलरूप से राजस्थान के रहने वाले थे। दोनों ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर किराना कारोबारी अजय अग्रवाल के घर पर डाका डाला था। मथुरा से 50 किमी दूर टैंटीगांव में 23 अप्रैल की रात उनके घर पर परिवार को बंधक बनाकर डकैती डाली थी। डकैतों के एनकाउंटर की खबर लगने के बाद कारोबारी ने कहा- मजा आ गया, पुलिस ने बढ़िया काम किया। वारदात के बाद SSP श्लोक कुमार ने डकैतों की तलाश के लिए 17 टीमें बनाई थीं। पुलिस को डकैतों के यमुना एक्सप्रेस-वे के पास होने का इनपुट मिला। पुलिस ने घेराबंदी कर ली। गुरुवार सुबह 7 बजे पल्सर बाइक से आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार यूटर्न लेकर भागने लगे। इस दौरान बेकाबू होकर उनकी बाइक गिर गई। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर में स्वाट टीम प्रभारी अजय वर्मा और हेड कांस्टेबल दुर्ग विजय भी घायल हुए हैं। दोनों को गोली लगी है। डकैत धर्मवीर पर मथुरा के अलावा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में डकैती, हत्या की कोशिश, छिनैती, चोरी समेत 16 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, डकैत पप्पू पर मेरठ, फिरोजाबाद, मथुरा के अलावा हरियाणा और दिल्ली में डकैती समेत 11 मुकदमे दर्ज हैं।

कारोबारी बोला- पुलिस ने बदमाशों को मारकर बढ़िया काम किया

वहीं अजय अग्रवाल ने बताया- 23 अप्रैल को मेरे घर में डकैती हुई थी। आज सूचना मिली है कि उनमें से दो बदमाश मार दिए गए हैं। इस खबर को सुनने के बाद से मैं और मेरा परिवार खुश है । पुलिस ने बढ़िया काम किया है। गांव वालों के अनुसार- अजय अग्रवाल का 2 हजार स्कावयर फिट का मकान है, उसी के अंदर छोटी सी दुकान है। जिसमें किराने का सामान बेचा जाता है। किराने की दुकान से ही परिवार का खर्च चलता है। उनके गांव में करीब 15 हजार की आबादी है।

23 अप्रैल को कारोबारी के घर डाका डाला था

मथुरा के टैंटीगांव में 23 अप्रैल की रात 12.30 बजे 5 नकाबपोश बदमाश पहुंचे। किराना व्यवसायी अजय अग्रवाल के घर छत के रास्ते घुसे। घर में मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया। बदमाशों ने अजय अग्रवाल, उनके पिता प्रेम प्रकाश अग्रवाल, पत्नी अनीता अग्रवाल और 6 साल की मासूम बच्ची उमा को रस्सियों से बांध दिया। गन प्वाइंट पर लेकर व्यापारी से लॉकर की चाबी ली।

पृष्ठ 01 का शेष...

निशांत समेत...

समर्थक जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं। पूरे रास्ते फूलों की बारिश की जा रही है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए महिलाएं बैरिकेडिंग के अंदर खड़ी होकर इंतज़ार कर रही हैं। धूप से बचने के लिए महिलाएं हाथों में लिए बैनर-पोस्टर से खुद को छिपाती नजर आईं। केंद्रीय ग-ह मंत्री अमित शाह गांधी मैदान में बने मुख्य मंच पर पहुंच गए हैं। निशांत ने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंच गए हैं। गांधी मैदान में हो रहे कार्यक्रम के लिए वीआईपी की एंट्री के लिए अलग से गेट बनाया गया है। जिससे सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक अंदर जा रहे हैं। इस गेट पर भी गाड़ियों की लंबी कतार है। सम्राट कैबिनेट विस्तार में आज 32 मंत्री शपथ ले रहे हैं। जिसमें बीजेपी कोटे से 15 और जदयू से 13 विधायक मंत्री बन रहे हैं। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांधी मैदान पहुंच गए हैं। राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, ₹आज बिहार एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सहित एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। बंगाल में मिली जीत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, साथ ही श्रमिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जो हमें गर्व का अनुभव कराती है। बिहार मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों की लाइव मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (ICCC) से लगातार की जा रही है। पटना स्मार्ट सिटी की टीम, तकनीकी विशेषज्ञ एवं पुलिस विभाग के अधिकारी पूरे आयोजन की क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

जाति तब खत्म...

उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को सफल बनाने के लिए लोगों को शिक्षित करना और उनकी भागीदारी जरूरी है। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जनसंख्या नियंत्रण उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जबरन नसबंदी कराई गई, जिससे लोगों में गुस्सा हुआ और बाद में सरकार को हार का सामना करना पड़ा। UCC को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। उत्तराखंड में ऐसा कानून आ चुका है और अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्य-दर-राज्य यह आगे बढ़ रहा है। शायद एक दिन पूरे देश में लागू हो जाए। लोकतंत्र में फैसले धीरे-धीरे होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 142 करोड़ लोग मिलकर फैसला करते हैं। जाति व्यवस्था पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि पहले समाज बदलेगा, तभी राजनीति बदलेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि केवल जाति भूलने की बात न करें, बल्कि ऐसा व्यवहार करें जैसे जाति है ही नहीं। उन्होंने अंतरजातीय संबंध और विवाह को बढ़ावा देने की बात कही और 1942 में महाराष्ट्र में हुए एक अंतरजातीय विवाह का उदाहरण दिया, जिसे बीआर आंबेडकर और एमएस गोलवलकर ने आशीर्वाद दिया था।

बंगाल गवर्नर...

108 सीटें हासिल करने वाली एक्टर विजय की पार्टी से राज्यपाल ने बहुतम के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन दिखाने को कहा है। विजय की पार्टी के पास 113 विधायक हैं, जो बहुमत से 5 कम है। तमिलनाडु में विजय को कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों और मुस्लिम लीग का समर्थन है। AIADMK ने अपने 28 विधायकों को पुडुचेरी शिफ्ट कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, जिसमें AIADMK सरकार बनाए और DMK बाहर से समर्थन दे। छोटे दलों का समर्थन भी इस फॉर्मूले का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। तमिलनाडु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के अध्यक्ष केएम कादर मोहिदीन चेन्नई में DMK मुख्यालय 'अन्ना अरिवलयम' पहुंचे। AIADMK के जनरल सेक्रेटरी के. पलानीसामी पुडुचेरी के पूरन-कुप्पम स्थित एक निजी रिसॉर्ट में पहुंचे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तमिलनाडु के AIADMK के 28 विधायक इसी होटल में ठहरे हुए हैं। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मौजूदा स्थिति कांग्रेस की रणनीति की गलती की वजह से बनी है। गुवाहाटी में अजमल ने कहा- असम चुनाव नतीजों पर विपक्ष की जो हालत हुई है, वह कांग्रेस की योजना की गलती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। AIUDF प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने साफ कहा- कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती। असम चुनाव परिणामों के बाद राज्य की राजनीति में विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। AIUDF और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। केरल विधानसभा चुनाव में LDF की बड़ी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और CPI(M) पोलित ब्यूरो सदस्य पिनराई विजयन ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं और UDF को जीत की बधाई देते हैं।

काशी में क्रूज से गंगा में गिरा युवा नेता, मौत

सेल्फी लेते समय पैर फिसला, 7 घंटे बाद शव मिला

तमसा संकेत, एजेंसी

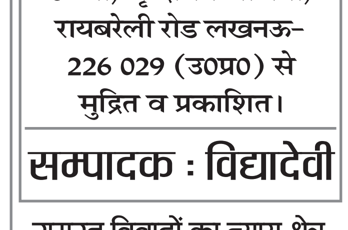
हर्षवर्धन ठाकुर, मृतक

वाराणसी। वाराणसी में क्रूज से सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवा नेता गंगा नदी में गिर गए। नदी के तेज बहाव और अंधेरा के चलते देर रात उनको खोजा नहीं जा सका। गुरुवार सुबह एनडीआरएफ ने फिर सर्चिंग शुरू की। करीब 7 घंटे बाद शव बाहर निकाला जा सका। हादसा बुधवार देर रात की है। मृतक की पहचान ग्रेटर नोएडा के हर्षवर्धन ठाकुर के रूप में हुई है। वह बीजेपी समर्थित भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के प्रदेश मंत्री थे। वह अपने 5 दोस्तों के साथ काशी घूमने पहुंचे थे। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हर्षवर्धन ठाकुर (27) बुधवार शाम को अपने पांच साथियों कुशाग्र सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, विपुल कुमार, जीत सिंह, ललित कुमार के साथ वाराणसी पहुंचे थे। बुधवार रात करीब 12.30 बजे सभी दोस्त गंगा घाट पर पहुंचे थे। दोस्त ललित ने बताया- हम लोगों को तड़के 3 बजे होने वाली मंगला आरती में शामिल होना था। इसलिए हम आधी रात को ही घाट पर पहुंच गए थे। मान घाट पर हम लोग आरती के पहले घूमने लगे। घाट पर कई क्रूज खड़े थे। हर्षवर्धन उस क्रूज पर स्नैप (सेल्फी) बनाने के लिए चढ़ गए। उनके दोनों हाथों में फोन थे। एक क्रूज के ऊपर चढ़कर उन्होंने सेल्फी ली और वीडियो बनाए। इसके बाद वह दूसरे क्रूज पर जाने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया और वह गंगा में गिर गए।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकिाशत लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676